

"एमएसएमई और स्टार्ट-अप हितधारक परामर्श बैठक"

सिडबी को 3 गुना वृद्धि करनी चाहिए - सचिव, डीएफएस, एमओएफ, भारत सरकार

सिडबी ने 21 नवंबर, 2023 को गुरुग्राम, हरियाणा में एक आउटरीच कार्यक्रम "एमएसएमई और स्टार्ट-अप हितधारक परामर्श बैठक" का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 350+ से अधिक स्टार्टअप/एमएसएमई/लीड इंडस्ट्री एसोसिएशन/रेटिंग एजेंसियों और एमएसएमई पारिस्थिति की तंत्र की सेवा करने वाले अन्य सक्षमकर्ताओं की भागीदारी देखी गई। इसका उद्देश्य सेवा की पहुंच और प्रभावशीलता को बढ़ाने के साथ-साथ इस क्षेत्र की आकांक्षाओं और नए भारत के प्रति उनकी तैयारी के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई जिसमें सिडबी की डिजिटल पेशकश सहित स्टार्टअप, एमएसएमई, ई-मोबिलिटी ओईएम और एग्रीगेटर्स को प्रदर्शित किया गया और आगंतुकों को समझाया गया। प्रतिभागियों ने एक पसंदीदा विकल्प के रूप में ईवी के लिए अपने एक्सपोजर की सराहना की और एमएसएमई से अभिनव पेशकशों के प्रति अपने दृष्टिकोण को व्यापक बना सकता है। सिडबी ने "एक्सप्रेस लोन" उत्पाद पर लाइव प्रदर्शन किया जिसमें सिडबी ने टीएटी को महीनों से घटाकर मिनटों तक कर दिया है।

वित्त मंत्रालय के डीएफएस सचिव श्री विवेक जोशी (आईएएस) मुख्य अतिथि थे और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव श्री सुभाष चंद्र लाल दास (आईएएस) सम्मानित अतिथि थे।

यह कार्यक्रम मंथन सत्र के साथ शुरू हुआ, जिसमें प्रमुख उद्योग संघों ने एमएसएमई द्वारा ऋण और गैर-वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए अपने दृष्टिकोण साझा किए। एसोसिएशनों ने सिडबी की अनुकरणीय सेवा को याद किया, विशेष रूप से पिछले कुछ वर्षों में जवाबदेही, डिजिटलीकरण को अपनाने (जिससे टीएटी में कमी आई है) और प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं को कम करने के मामले में बदलाव आया है, जिससे सिडबी में अंतिम मील का प्रवेश संभव हो गया है। श्री राजीव चावला, श्री राकेश छाबड़ा और श्री जे पी मल्होत्रा ने एमएसएमई की आवाज का प्रतिनिधित्व किया।

गुरुग्राम के उपायुक्त श्री निशांत कुमार यादव ने सभा को संबोधित किया और राज्य के अधिकारियों से समर्थन की निरंतरता का आश्वासन दिया। श्री यादव ने कहा कि गुरुग्राम के उद्यमी लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी क्षमता स्थापित की है और यह गति जारी रहनी चाहिए।

सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस. रमण ने कहा कि डीएफएस सचिव और एमएसएमई मंत्रालय में सचिव की उपस्थिति एमएसएमई को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। श्री रमण ने उल्लेख किया कि हमारा जोर "डिजिटलीकरण" और "उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र को हरा-भरा" करने पर रहा है। सिडबी मांग और आपूर्ति पक्ष के अंतर का आकलन कर रहा है और इन्हें दूर करने के लिए वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवाओं का प्रावधान किया है। श्री रमण ने उल्लेख किया कि सिडबी उद्योग संघों की प्रतिक्रिया और इनपुट को महत्व देता है जो अधिक

उत्तरदायी बनने में मदद करता है। श्री रमन ने उल्लेख किया कि सिडबी एमएसएमई के पंजीकरण, उनके द्वारा वित्त तक पहुंच के साथ-साथ क्रेडिट पहुंच को लोकांतरिक बनाने के लिए जीएसटी डेटा का लाभ उठाने पर काम कर रहा है। श्री रमन ने उल्लेख किया कि भारत सरकार की इस अपेक्षा के अनुरूप कि सिडबी को एमएसएमई के लिए सबसे बड़े प्रत्यक्ष ऋणदाता के रूप में विकसित होना चाहिए, सिडबी ने एबीसी दृष्टिकोण की रणनीति बनाई है। इसमें **ऐप आधारित, शाखा आधारित और सह-भागीदार आधारित ऋण शामिल हैं।**

एमएसएमई मंत्रालय में सचिव **श्री एस.सी.एल. दास** ने कहा कि मंत्रालय एमएसएमई के विकास और फलने-फूलने के लिए एक मजबूत और सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री दास ने स्थिरता के साथ विकास के इर्द-गिर्द बुनी गई मंत्रालय की अभिनव पेशकशों पर जोर दिया। श्री दास ने पीएम विश्वकर्म जैसी केन्द्रीय योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मंत्रालयों के बीच बढ़ते समन्वय पर प्रकाश डाला। श्री दास ने यह भी उल्लेख किया कि मंत्रालय हरित निवेश को उत्प्रेरित करने और भारत के राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (एनडीसी) में योगदान करने के लिए नई योजनाएं शुरू करने के लिए तैयार है। श्री दास ने सिडबी के बढ़ते योगदान की सराहना की और सुझाव दिया कि पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) पहलुओं को संपूर्ण उद्यम ऋण में शामिल करने और मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता है।

वित्त मंत्रालय में सचिव **श्री विवेक जोशी** ने भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के महत्व की वकालत की और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के विकास और वृद्धि के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री जोशी ने एमएसएमई को विशेष रूप से डिजिटलीकरण, क्रेडिट गारंटी, ईसीएलजीएस (कोविड राहत के रूप में) के माध्यम से ऋण प्रवाह को मजबूत करने में सिडबी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को भी स्वीकार किया। श्री जोशी ने बैंकिंग और डिजिटल उपकरणों के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने पर भारत सरकार के जोर पर भी प्रकाश डाला। श्री जोशी ने यह भी बताया कि किस प्रकार बैंकों को पीएमस्वनिधि के तहत स्ट्रीट वेंडर्स तक पहुंचने के लिए सक्रिय रूप से लगाया गया है और कारीगरों को समग्र सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विश्वकर्म भी किया गया है। श्री जोशी ने प्रदर्शनी की सराहना की जो देश की शुद्ध शून्य यात्रा की ओर बढ़ती अभिमुखता और मांग को दर्शाती है। श्री जोशी ने उद्यमियों से सिडबी द्वारा एक सप्रेस ऋण, परिवहन के पसंदीदा माध्यम के रूप में ई-मोबिलिटी आदि जैसी सेवाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। सिडबी की भूमिका की सराहना करते हुए श्री जोशी ने सिडबी के पदचिह्नों को तिगुना करने की उम्मीदें जताईं। एमएसएमई और डीएफएस मंत्रालय एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए पूरे दिल से समर्थन देना जारी रखेंगे, विशेष रूप से पिरामिड के निचले स्तर पर।

गणमान्य व्यक्तियों ने अपने 50केईवी4ईसीओ कार्यक्रम के तहत एनसीआर में सेवाएं प्रदान करने के लिए सिडबी द्वारा समर्थित ईवी को हरी झंडी दिखाकर प्रतिभागियों की खुशी को बढ़ाया। श्री विवेक जोशी और श्री एससीएल दास ने सिडबी की डिजिटल यात्रा, 4ई योजना, गति और उद्यम ऋण के तहत सहायता प्रदान करने वाले 08 स्टार्टअप/एमएसएमई को स्वीकृत पत्र सौंपा। 50केईवी4ईसीओ कार्यक्रम के तहत, एक सेवा प्रदाता के रूप में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को मंजूरी पत्र सौंपा गया था और बाजार बनाने के लिए प्रतिस्पर्धी दर पर वाणिज्यिक ईवी के अधिग्रहण का समर्थन करने के लिए "सीकर्स फाइनेंस" को संवितरण चेक भी सौंपा गया था।

इस अवसर पर स्टार्टअप/एमएसएमई/एनबीएफसी को 57 करोड़ रुपये की संचयी मंजूरी सौंपी गई।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के बारे में:

सिडबी, भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत 2 अप्रैल 1990 को स्थापित, एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन, वित्तपोषण और विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान है। सिडबी बैंकों को पुनर्वित्त, क्रेडिट गारंटी कार्यक्रम, एमएफआई क्षेत्र का विकास, उद्यम पूंजी/एआईएफ निधियों में योगदान, एमएसएमई रेटिंग, डिजिटल उधार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने आदि सहित विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र के लिए वित्तीय सेवाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बैंक ऊर्जा कुशल परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक, एडीबी, जीआईजेड, एफसीडीओ, जेआईसीए, एएफडी, केएफडब्ल्यू आदि जैसे बहुपक्षीय संस्थानों के समर्थन का उपयोग करके 2005-06 से एमएसएमई में ऊर्जा दक्षता (ईई) की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इसके अलावा, सिडबी अपने एकीकृत, अभिनव और समावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों में नागरिकों के जीवन को छू रहा है। चाहे वह पारंपरिक, घरेलू छोटे उद्यमी, निचले स्तर के उद्यमी हों या उच्च अंत ज्ञान आधारित उद्यमी हों, सिडबी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न ऋण और विकास तामक उपायों के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के जीवन को प्रभावित किया है।

अधिक जानने के लिए, देखें: <https://www.sidbi.in>



